



## स्मार्ट गाँव : प्रौद्योगिकी आधारित समावेशी विकास

के. के. त्रिपाठी  
अनन्या अरझरे

स्मार्ट गाँव की अवधारणा ग्रामीण विकास के एक समग्र मॉडल के रूप में उभर रही है, जो प्रौद्योगिकी, सुशासन और सामुदायिक सहभागिता को एक साथ जोड़ती है। भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई-संजीवनी, ई-नाम तथा बहुदेशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों जैसे- डिजिटल सार्वजनिक मंच ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की पहुँच और प्रभावशीलता को नई गति प्रदान कर रहे हैं। स्मार्ट गाँव का उद्देश्य केवल डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अवसरों का विस्तार और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है।

# भा

रत की विकास-यात्रा इसके गाँवों के परिवर्तन से गहराई से जुड़ी हुई है। देश की लगभग 87 करोड़ (63 प्रतिशत) आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और 6.5 लाख गाँवों में फैली हुई है। कृषि आज भी देश के लगभग 45 प्रतिशत कार्यबल को आजीविका प्रदान करती है, फिर भी अनेक

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी लाभों का वितरण लंबे समय तक विलंब, रिसाव और सीमित जवाबदेही जैसी चुनौतियों से प्रभावित रहा है।

### स्मार्ट गाँव : अवधारणा और आवश्यकता

स्मार्ट सिटीज मिशन ने शहरी पुनरुत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की। किंतु संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ते भारत के लिए स्मार्ट गाँव की अवधारणा

लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में संयुक्त सचिव और सह-लेखिका इंटरन हैं। ई-मेल: tripathy123@rediffmail.com

ग्रामीण परिवर्तन का एक समान रूप से महत्वपूर्ण मॉडल बनकर उभरी है। स्मार्ट गाँव केवल भौतिक अवसंरचना के विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक समग्र विकास मॉडल है जो प्रौद्योगिकी, संस्थागत सुदृढीकरण और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत कर जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आजीविका के अवसरों के विस्तार तथा आवश्यक सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और शासन जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करना है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों में तीव्र प्रगति ने लंबे समय से चली आ रही विकासात्मक बाधाओं को दूर करने के नए अवसर प्रदान किए हैं। जब गाँवों को विश्वसनीय डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा, ज्ञान संसाधनों और सशक्त स्थानीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त होता है, तो वे नवाचार और सेवा प्रदायगी के सशक्त केंद्रों के रूप में विकसित हो सकते हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी समावेशी विकास और ग्रामीण समृद्धि की एक प्रभावी उत्प्रेरक बन जाती है।

### स्मार्ट गाँव की संरचना

स्मार्ट गाँव की अवधारणा तीन मूलभूत सिद्धांतों-सततता, समावेशन और प्रौद्योगिकी-सक्षमता पर आधारित है। इसका ढाँचा परस्पर जुड़े अनेक स्तंभों पर निर्मित है जिनमें विश्वसनीय डिजिटल कनेक्टिविटी, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सुदृढ ज्ञान अवसंरचना तथा नवाचार को अपनाने और बनाए रखने में सक्षम

स्थानीय अर्थव्यवस्था शामिल हैं। ये सभी तत्व सतत विकास लक्ष्यों की भावना के अनुरूप हैं, जो इस बात पर बल देते हैं कि दीर्घकालिक विकास विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावी अभिसरण पर निर्भर करता है।

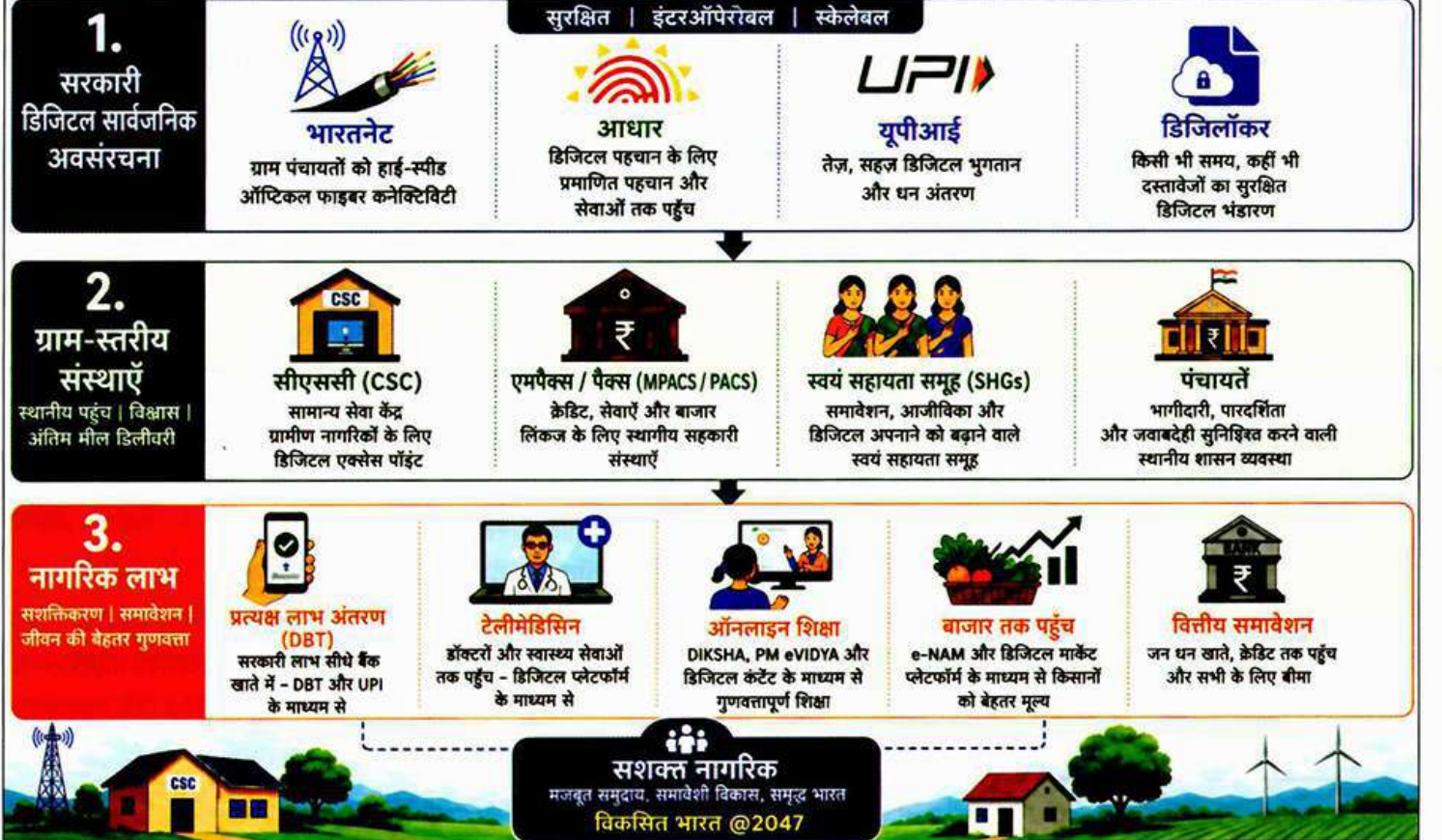
स्मार्ट गाँव की पहचान केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहाँ के लोग और संस्थाएँ प्रौद्योगिकी का कितना प्रभावी उपयोग कर पाते हैं। वास्तविक कल्याणकारी लाभ तब प्राप्त होते हैं जब समुदाय शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार पहुँच और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए डिजिटल साधनों का उपयोग करने में सक्षम हों। इसलिए सामुदायिक सहभागिता और विकेन्द्रीकृत निर्णय स्मार्ट गाँव मॉडल के केंद्रीय तत्व हैं। इस मॉडल में प्रौद्योगिकी एक सक्षमकारी माध्यम की भूमिका निभाती है जबकि सशक्त स्थानीय संस्थाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि विकास समावेशी, जवाबदेह और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे। इस प्रकार स्मार्ट गाँव की अवधारणा 73वें संविधान संशोधन की लोकतांत्रिक भावना को सुदृढ करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण परिवर्तन के प्रमुख वाहक के रूप में सशक्त बनाती है।

### भारत में नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र

स्मार्ट गाँवों को ग्रामीण नवाचार और समावेशी विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु भारत ने एक सुदृढ नीतिगत ढाँचा तैयार किया है। डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख पहलों ने

## तकनीक कैसे ग्रामीण नागरिकों तक पहुँचती है

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से रोज़मर्रा के लाभ तक



तालिका 1 : स्मार्ट गाँव – क्षेत्रवार क्रांतिकारी लाभ

क्षेत्र	क्रांतिकारी लाभ
डिजिटल अवसंरचना	<ul style="list-style-type: none"> <li>विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल पहुँच स्मार्ट गाँवों की आधारशिला हैं।</li> <li>कॉमन सर्विस सेंटर जैसे संस्थान स्थानीय सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जहाँ नागरिक दस्तावेजीकरण, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।</li> </ul>
ई-गवर्नेंस	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रौद्योगिकी के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का निर्बाध एवं प्रभावी क्रियान्वयन संभव हुआ है।</li> <li>प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली रिसाव को कम करती है, पारदर्शिता बढ़ाती है तथा लाभार्थियों तक समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करती है।</li> </ul>
स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>टेलीमेडिसिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज शहरी विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।</li> <li>डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख और दूरस्थ निदान स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता तथा पहुँच को बेहतर बनाते हैं।</li> </ul>
शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्मार्ट गाँव ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, डिजिटल कक्षाओं तथा कौशल विकास मंचों तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं।</li> <li>इससे शैक्षिक असमानताओं को कम करने तथा ग्रामीण युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने में सहायता मिलती है।</li> </ul>
आजीविका एवं आय	<ul style="list-style-type: none"> <li>ई-नाम जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित मंच किसानों को बाजार संबंधी जानकारी, बेहतर मूल्य खोज तथा व्यापक विपणन अवसर उपलब्ध कराते हैं।</li> <li>सटीक कृषि, मौसम पूर्वानुमान तथा डिजिटल सलाहकारी सेवाएँ उत्पादकता और कृषि लचीलेपन को बढ़ाती हैं।</li> <li>भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने CSC आधारित पंजीकरण, आधार-सक्षम सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन, 15,000 मूल्य के टूलकिट हेतु ई-वाउचर, डिजिटल ऋण प्रसंस्करण तथा डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार को सुदृढ़ किया है।</li> </ul>

कनेक्टिविटी का विस्तार, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा और ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाकर ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन की आधारशिला रखी है।

इस परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ भारतनेट है, जिसने लगभग 6.93 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। वर्ष 2025 तक इस परियोजना के तहत 12.81 लाख फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्शन तथा 1.04 लाख से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके थे। परिणामस्वरूप ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2015-16 के 11.5 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2024 तक 40.5 करोड़ से अधिक हो गई, जबकि डेटा की लागत 2014 में 269 प्रति जीबी से घटकर 2025 तक लगभग 8-10 प्रति जीबी रह गई। जनवरी 2025 में प्रारंभ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 ने इस डिजिटल विस्तार को और गति प्रदान की है।

भौतिक अवसंरचना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा सौभाग्य योजना जैसी पहलों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जिन्होंने ग्रामीण संपर्क और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति को बढ़ावा दिया है। ये दोनों ही तकनीकी समाधान अपनाने के लिए आवश्यक आधारभूत शर्तें हैं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका

मिशन ने सामुदायिक संस्थाओं को सशक्त बनाते हुए स्थानीय-स्तर पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग की क्षमता विकसित की है।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अभिसरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और डिजिटल लॉकर जैसे मंच शामिल हैं, ने सेवाओं की पारदर्शी एवं दक्षतापूर्ण डिलीवरी को सुदृढ़ किया है तथा लक्षित कल्याणकारी वितरण की आधारशिला के रूप में कार्य किया है।

आज योजनाओं का अभिसरण ग्रामीण परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक ही लाभार्थी प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) से संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकता है, जन धन खाते के माध्यम से भुगतान हासिल कर सकता है, ई-संजीवनी के जरिए चिकित्सकीय परामर्श ले सकता है तथा राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) पर अपनी कृषि उपज का विपणन कर सकता है। सेवाओं का यह निर्बाध एकीकरण भारत के ग्रामीण डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है।

## सौर सहकारिता का सफल मॉडल 'धुंडी'

वर्ष 2016 में गुजरात के एक छोटे से गाँव धुंडी ने एक अभिनव पहल के माध्यम से किसानों को केवल कृषि उत्पादक ही नहीं, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा उद्यमी भी बना दिया। अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के सहयोग से स्थापित धुंडी सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी विश्व की पहली सौर सिंचाई सहकारी समिति बनी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की दो प्रमुख चुनौतियों—सिंचाई के लिए अनियमित बिजली आपूर्ति और बढ़ती कृषि लागत का समाधान करना था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-आधारित स्वच्छ ऊर्जा नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।



क्षेत्र के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत थे, जो व्यक्तिगत रूप से सौर ऊर्जा अवसंरचना की लागत वहन करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने सहकारी मॉडल अपनाकर संसाधनों का साझा उपयोग किया और कुल 56.4 किलोवाट पीक क्षमता वाले छह सौर पंप स्थापित किए। सहकारी समिति ने मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के साथ 25 वर्ष का विद्युत क्रय समझौता किया, जिसके तहत किसान अतिरिक्त बिजली को निर्धारित दर पर ग्रिड को बेच सकते थे। इससे सामुदायिक स्वामित्व वाली स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना का विकास संभव हुआ।

इस मॉडल ने किसानों के लिए दोहरी आय का स्रोत तैयार किया। किसान सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं। इससे डीजल पंपों पर निर्भरता कम हुई, परिचालन लागत घटी और दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध होने लगी। प्रारंभिक दौर में उच्च लागत और नई तकनीक को लेकर किसानों में संकोच था, किंतु प्रशिक्षण, प्रदर्शन परियोजनाओं और संस्थागत सहयोग ने धीरे-धीरे उनका विश्वास बढ़ाया। इस अनुभव ने सिद्ध किया कि स्मार्ट ऊर्जा समाधान और सामूहिक प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आय और समृद्धि का आधार बन सकते हैं।

धुंडी मॉडल यह दर्शाता है कि सहकारी संस्थाएँ, तकनीकी नवाचार और रणनीतिक साझेदारियाँ मिलकर किस प्रकार एक सशक्त ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकती हैं। साथ ही, यह मॉडल स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका सुदृढीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

### प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में स्मार्ट गाँव

स्मार्ट गाँवों का विकेन्द्रीकृत प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में उभरना पाँच परस्पर जुड़े क्षेत्रों (तालिका-1) के माध्यम से समझा जा सकता है। ये सभी क्षेत्र मिलकर एक ऐसे एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी कल्याणकारी परिणामों, सेवा वितरण की दक्षता और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। गाँवों को प्रौद्योगिकी केंद्रों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया इन परस्पर पूरक क्षेत्रों के प्रभावी एकीकरण पर निर्भर करती है।

### डिजिटल सेवाएँ और ग्रामीण सशक्तीकरण

कॉमन सर्विस सेंटर ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुँच को संस्थागत रूप प्रदान किया है। अप्रैल 2025 तक देश में 5.34 लाख CSC संचालित थे, जिनमें से 4.17 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये केंद्र आधार, बैंकिंग, बीमा, फसल बीमा तथा विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या 2013 के 11 करोड़ से बढ़कर 2024 में 176 करोड़ हो गई है। इस प्रणाली ने रिसाव को कम करते हुए 3.48 लाख करोड़ की

संचयी बचत सुनिश्चित की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 98 प्रतिशत मजदूरी भुगतान समय पर किए जा रहे हैं, जबकि प्रौद्योगिकी-सक्षम लक्षित वितरण के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 1.85 लाख करोड़ की बचत दर्ज की गई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष्मान भारत के अंतर्गत ई-संजीवनी ने 1.76 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को जिला एवं तृतीयक अस्पतालों से जोड़ते हुए वर्ष 2025 के मध्य तक लगभग 37.2 करोड़ टेली-परामर्श उपलब्ध कराए हैं। इस सेवा में 57 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में गतिशीलता संबंधी बाधाओं के कम होने का संकेत है। इसी प्रकार, DIKSHA, PM eVIDYA तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) ने डिजिटल शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मार्च 2024 तक PMGDISHA के अंतर्गत 6.39 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जा चुका था। दूसरी ओर, राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) ने 1,389 मंडियों, 1.78 करोड़ किसानों और 2.62 लाख व्यापारियों को एकीकृत करते हुए कृषि विपणन को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया है।

## सहकारिताएँ और सामुदायिक संस्थाएँ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जिनसे 16 करोड़ से अधिक किसान सदस्य जुड़े हैं, ग्रामीणों और डिजिटल अवसंरचना के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती हैं। ऋण वितरण से आगे बढ़ते हुए PACS अब कृषि उत्पादों के संकलन, विपणन तथा डिजिटल सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित हो रही हैं। संशोधित मॉडल उपविधियों के अंतर्गत 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दिए जाने के बाद इनका बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में रूपांतरण सहकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है।

‘सहकार से समृद्धि’ विज्ञान के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2027 तक पंचायत-स्तर पर 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। अप्रैल 2025 तक 19,619 MPACS का पंजीकरण हो चुका था, जबकि 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मॉडल उपविधियों को अपनाया है। साथ ही, 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की 67,930 PACS को कंप्यूटरीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए ₹865.81 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

कोऑपरेटिव स्टैक से जुड़ने के बाद PACS तेजी से विकेन्द्रीकृत, सामुदायिक स्वामित्व वाले प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में विकसित हो रही हैं। ये संस्थाएँ DBT सेवाओं, बैंकिंग सुविधाओं, टेलीमेडिसिन तथा अन्य डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही हैं, जबकि स्थानीय समुदाय का विश्वास इनके कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाता है। ऊर्जा, कृषि और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में इनके नवाचारपूर्ण प्रयोग स्मार्ट गाँवों के विकास को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।

## चुनौतियाँ और सीमाएँ

उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद स्मार्ट गाँवों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। लिंग, आयु, आय, सामाजिक समूह और भौगोलिक स्थिति पर आधारित डिजिटल विभाजन अब भी एक गंभीर बाधा है। ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से स्मार्टफोन स्वामित्व, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट उपयोग और सामाजिक प्रतिबंधों के कारण अपेक्षाकृत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में केवल 38 प्रतिशत परिवारों को ही डिजिटल रूप से साक्षर माना जाता है। ASER रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 26.9 प्रतिशत लड़कियों के पास स्मार्टफोन हैं, जबकि लड़कों में यह अनुपात 36.2 प्रतिशत है, जो डिजिटल अवसरों तक असमान पहुँच को दर्शाता है।

भारतनेट को भी अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और रखरखाव संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं—जैसे PM-KISAN, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मनरेगा (VB-G RAM G) के लिए अलग-अलग पोर्टलों और शिकायत निवारण प्रणालियों के कारण नागरिकों को कई मंचों पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा गोपनीयता संबंधी ढाँचों को अभी भी सुदृढ़ करने की

आवश्यकता है, जबकि कम माँग वाले क्षेत्रों में CSCs की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त नीतिगत समर्थन अपेक्षित है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए अवसंरचना, संस्थागत सुधार और सामुदायिक सशक्तीकरण में समन्वित निवेश आवश्यक है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 इस दिशा में नया संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है, किन्तु इसकी सफलता विश्वसनीय कनेक्टिविटी, दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर सेवा गुणवत्ता तथा आवश्यकता पड़ने पर उपग्रह-आधारित समाधानों के विस्तार पर निर्भर करेगी। साथ ही, डिजिटल अवसंरचना के समान ही डिजिटल साक्षरता को भी प्राथमिकता देनी होगी। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ तथा PACS जैसी संस्थाएँ उचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिलने पर प्रभावी डिजिटल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा सकती हैं।

## आगे की राह

योजनाओं का अभिसरण केवल नीति-स्तरीय लक्ष्य न रहकर व्यावहारिक क्रियान्वयन का आधार बनना चाहिए। MPACS की नई संरचना ऋण, कृषि निवेश, डिजिटल सेवाओं और बाजार पहुँच को एकीकृत करने का प्रभावी ढाँचा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, एग्री-स्टैक और MPACS का एकीकरण इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कृषि प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी और डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए ONDC तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे खुले डिजिटल मंच ग्रामीण नवाचार को और गति दे सकते हैं। विकसित भारत@2047 के परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट गाँव विकास की परिधि पर स्थित अवधारणा नहीं, बल्कि उसके केंद्र में हैं।

स्मार्ट गाँवों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार पहुँच और वित्तीय समावेशन जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि ग्रामीण भारत तक समान रूप से पहुँचे। भारतनेट, CSC, DBT, ई-संजीवनी, ई-नाम और MPACS जैसे तंत्रों ने पिछले दशक में एक मजबूत आधार तैयार किया है। अब सबसे बड़ी आवश्यकता इन सभी प्रणालियों के निर्बाध अभिसरण की है, ताकि वे ग्राम स्तर पर एकीकृत रूप से कार्य कर सकें।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की PURA (Provision of Urban Amenities in Rural Areas) अवधारणा ने स्पष्ट किया था कि केवल कनेक्टिविटी से सतत विकास संभव नहीं होता। सामुदायिक सहभागिता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा MPACS और स्वयं सहायता समूहों जैसी विश्वसनीय स्थानीय संस्थाओं पर आधारित स्मार्ट गाँव, ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने और विकसित भारत के निर्माण में ग्रामीण भारत को अग्रणी भूमिका दिलाने का व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। □